(SHRI H.K.L. BHAGAT): (a) to (c) There has been a mixed trend in the behaviour of prices of essential commodities in Delhi during the last two months. Between 28.8.1987 and 29.10.1987, retail prices of certain commodities like some pulses, edible oils (except vanaspati) and some spices and condiments have shown an increase while prices of some other commodities like atta, maida, suji, vanaspati, turmeric and some vegetables have declined. Prices of rice, wheat, urad dal, moong dal, matches, bread, salt and potatoes have remained steady during this period.

2. The rise in the prices of certain es sential commodities may be attributed to the seasonal factors, fall in production of some commodities and the widespread drought conditions in large pacts of the country.

3. The Delhi Adminisration has taken a number of steps to check the rise in prices of essentia! commodities. The Pub lic Distribution System has been streng thened and at present approximately 3200 Fair Price Shops are supplying essential commodities such as wheat, rice, sugar, imported edible oils, etc., to consumers against ration cards. In addition the num ber of mobile vans and static outlets which are selling essential commodities in dif- different localities has been increased to 188 and 227 respectively. Onions and potatoes are also sold through the mobile and static outlets of Super Bazar, Delhi State Civil Supplies Corporation, Kend-riya Bhandar and Delhi Consumer Cooperative Wholesale Store at reasonable prices. During the last two months, allocation of imported edible oil has been increased substantially for selling to con- sumers through Public Distribution System and retail parties of the nominated agencies mentioned above.

4. Periodic meetings are held with rep resentative of trade and industry at va rious levels to contain [reduce prices and to ensure availability of essential commo dities. Enforcement measures were tight ened by the Delhi Administration against hoarding and profiteering. During the current year 15th October 1987, 4983 checkings|raids were carried out, depart mental action was taken in 1464 cases and FIRs were lodged against 96 unscrupulous traders sand licensees.

किसानों को सहायता

*14. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबी के मौसम में उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों, विशेषकर बिहार के किसानों, को इस वर्ष बीज, खाद के ऋण प्रत्यक्षण तथा अन्य विशेष सहायता प्रदान करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ख) क्या सरकार किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक निःशुल्क उपलब्ध कराने का विचार रखती है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्य है ;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) भारत सरकार ने आगामी रबी मौसम में अधिक उत्पादन के लिये विभिन्न आदान सुलभ कराने की विशेष व्यवस्था की है । इसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

बीज :

बिहार सरकार ने 1987–88 के रबी मौसम में बुवाई के लिये गेहूं के तीन लाख क्विंटल बीजों की सप्लाई के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है । इस मांग को पूरा करने के लिये, राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से गेहूं के 3 लाख क्विंटल अप्रमाणित बीजों की सप्लाई की विशेष व्यवस्था की गई है जिसको अधिप्राप्ति भारतीय राज्य फार्म निगम के गोदामों से राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा की जायेगी । भारत सरकार ने आगामी रबी मौसम के लिये 103.74 रुपये प्रति क्विंटल की राजसहायता भी दी है । उपलब्ध सूचना के अनुसार,

राष्ट्रीय बीज निगम ने 50 प्रतिशत से अधिक बीजों की सप्लाई पहले ही कर दी हैं तथा शेष मात्रा 15 नवम्बर, 1987 तक सप्लाई कर दी जायेगी ।

उर्वरक और खाद :

आगामी रबी मौसम के लिये बिहार के वास्ते 3.70 लाख मीटरी टन उर्वरक पोषकों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है तथा विभिन्न योजनाओं से इसका पूरा आवंटन किया जा चुका है। उस राज्य सरकार से उर्वरकों की कमी की कोई शिकायत नहीं है ।

ऋण :

मानसून न आने और उसके परिणामस्वरूप पड़े सूखे के कारण सरकार कृषि ऋण के प्रवाह के लिये विशेष उपाय कर रही है। नाबार्ड ने सहकारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बकों को सलाह दी है कि वे बिहार सहित विभिन्न राज्यों में प्रभावित ऋण लेने वालों को जहां संभव हो सके लघुकालिक वैकल्पिक फसलें उगाने के लिय आवश्यक सहायता प्रदान करें। नाबार्ड ने एक बहुत विशेष मामले के रूप में वर्तमान वर्ष के लिये कुछेक रियायतें देने का भी निर्णय लिया है जिसका विशेष प्रयोजन आगामी रबी मौसम के लिये पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करना है। बिहार राज्य में पात्रता के 20 प्रतिशत तक चूक करने वाले छोटे किसान अब नई धन व्यवस्था के लिये पात्र समझे जाएंगे ।

प्रदर्शन

राज्य सरकार के पास ग्रामीण विस्तार कर्मियों की जनशक्ति के अतिरिक्त गैर सरकारी और सहकारी उर्वरक औद्योगिक यूनिटों के पास उपलब्ध विस्तार कर्मचारियों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य सरकार के कृषि विभाग के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि रबी मौसम में अधिक उत्पादन के लिये प्रौद्योगिकी अपनाने में किसानों को मदद देने हेतु प्रदर्शनों के काम को तेज करने के लिये साझी कार्यनीति अपनाई जा सके ।

पौध संरक्षण

कीटनाशी दवाइयों की सप्लाई के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् कृषि महत्व के कृमियों और रोगों पर नियंत्रण के जरिये कीटनाशी दवाइयों की लागत पर राजसहायता दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कीटनाशी दवाइयों की लागत पर 50 प्रतिशत राजहसहायता दी जाती है जो केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा 50–50 के आधार पर वहन की जायेगी । वर्ष 1987–88 के लिये बिहार राज्य सरकार ने दलहनों, तिलहनों और आलू के कृमियों तथा सभी फसलों को बचाने के लिये चूहों पर नियंत्रण हेतु केन्द्रीय सहायता के लिये अनुरोध किया था, जिसमें कीटनाशी दवाइयों पर केन्द्रीय हिस्सा 1461250 रुपये का था। इस राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है ।

1987–88 के रबी मौसम के दौरान तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिये बिहार को शत-प्रतिशत केन्द्रीय भागीदारी से शुरू की गई तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि (ट्रष्ट) कार्यक्रम योजना (ओ पी टी पी) के अंतर्गत 35.5 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। जिन मदों के लिये उक्त धनराशि आबंटित की गई है, उनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं ; —

1. 18 लाख रुपये की लागत से 6000 हैक्टेयर भूमि प्रदर्शन

2. 7 लाख रुपये की लागत से पौध संरक्षण सुरक्षा

3. 3 लाख रुपये की लागत से 1000 (संख्या) पौध संरक्षण उपस्करों का वितरण और

4. रेपसीड सरसों और तोरिया का उत्पादन बढ़ाने के लिये 7.5

लाख रुपये के परिव्यय से रेपसीड, सरसों और तोरिया की फसल में 3500 हैक्टेयर में कल्शियम सल्फट का प्रयोग ।

(ख) इस समय सरकार के पास किसानों को बीज, खाद और कीटनाशी दवाएं नि:शुल्क सुलभ कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Fair price shops to Drought-affected Villages

*15. SHRI SURENDRA SINGH THAKUR; Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state.-

(a) what steps have been taken by Government to supply food provisions to drought-affected villages in the rural and remote areas;

(b) whether fair price shops have been opened to supply food provisions *to* the villages affected bydrought;

(c) if the repy to part (a) above be in the affirmative, what are the details thereof; and

(d) if the reply to part (b) above be in the negative, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H.K.L. BHAGAT): (a) to (d) PDS has a key role in providing essential commodities to people particularly those beonging to vulnerable section of the society. This acquires special importance in the context of the drought situation prevailing in a large part of the country. Under the existing scheme of the PDS, the Central Government is responsible for procuring, storage and allocation etc. of food items, namely, wheat, rice, levy sugar and imported edible oils. States and U.Ts. are responsible for arranging their transportation from Central godowns for distributing these items through a network of fair price shops. The following steps have been taken by the Government for providing essential food items in drought affected areas:—.

(i) To meet the increased demand of foodgrains under PDS in the States which have been affected by drought and flood and to meet lean season demands, extra allocations of wheat and rice to the tune of 8.77 lakh tonnes and 1 82 lakh tonnes respectively have been made during the period from July to November 1987.

(ii) Allocation of imported edible oils for the PDS has been increased from 70,000 MTs in July, 1987 to 1.20 lakh MTs in August, 1987, 1.50 lakh MTs in September,' 1987 and 2.00 lakh MTs each in October and November, 1987.

(iii) 8.57 lakh MTs of sugar were released in the market in September, as well as October, 1987, as against 7.62 lakh tonnes allocated in August, 1987.

(iv) State Governments and U.T. Administration have been asked to identify hitherto uncovered areas and opsn additional fair price shops therein Since August, 1987, 2930 fair prica shops have been opened in drought affected areas.

(v) Department of Civil Supplies, have sanctioned financial assistance to the tune of Rs. 182.50 lakh for purchase of 73 additional mobile vans during 1987-88 for Uttar Pradesh, Raj-athan, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh and Chandigarh. In addition, States have been asked to press into service more mobile vans *to* cover areas where static fair price shops cannot be opened.

(vi) For proper supervision of distribution system, States have been advised to constitute advisory committees; consisting of elected representatives,, consumer organisations, industry, trade,, women representatives, voluntary organisations etc. at State, District, Subdivision levels and even at the Fair Price Shops level.

(vii) The States have also been asked' to undertake intensive monitoring of prices and availability of 23 essential-items like foodgrains, pulses, vegetables, milk, sugar edible oils, tea, coffe etc.